इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में शामिल होगा बड़नगर

भोपाल, 6 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां को छू रहा है. देश में मध्यप्रदेश का विशेष महत्व है. विकास के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार समाज के हर वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है. उज्जैन जिले का बड़नगर भी विकास में अग्रणी रहेगा.

बड़नगर अब इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन एरिया का भाग बनेगा. बड़नगर पर बाबा महाकाल सहित चंबल, शिप्रा और गंभीर नदियों का भी आशीर्वाद है. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि-पूजन किया है. टेक्सटाइल सेक्टर के इस मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का लाभ भी बड़नगरवासियों को मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बड़नगर क्षेत्र में संचालित गौशालाओं को नरवाई प्रबंधन के लिए मशीनें लेने में सहायता के उद्देश्य से स्वेच्छानुदान से अंश राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इससे नरवाई के निराकरण के साथ ही गौशालाओं को पर्याप्त भूसा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बड़नगर क्षेत्र के व्यायाम शालाओं को प्रोत्साहन स्वरूप एक-एक लाख रूपए देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव, नायीखेड़ी-नागदा-रतलाम मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनका आभार प्रकट करने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव का बड़नगरवासियों ने साफा और गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया.

सीएम ने की गेहूं पर बोनस की घोषणा

इन्दौर. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार गेहूं की खरीद अब 2625 प्रति क्विंटल की दर से करेगी. सरकार ने एमएसपी 2585 प्रति क्विंटल पर 40 बोनस देने का निर्णय लिया है. सीएम ने यह भी घोषणा की कि गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च तक कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें.

दिन में बिजली देने की योजना जारी रहेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के समय दिन में ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. रात में सिंचाई या अन्य कृषि कार्य करने में किसानों को जो परेशानियां होती हैं, उन्हें देखते हुए सरकार यह कल्याणकारी व्यवस्था आगे भी जारी रखेगी. उन्होंने बताया कि बड़वानी में हुई कृषि कैबिनेट के संकल्पों को सरकार लगातार पूरा कर रही है और किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं. सीएम ने इंदौर में निकलने वाली पारंपरिक गैर को लेकर भी लोगों को अग्रिम बधाई दी. उन्होंने कहा कि होली रंगों और आनंद का त्योहार है और हमें मिलकर देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति को जीवित रखना चाहिए.

यूपीएससी में सफल युवाओं को दी बधाई

इंदौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यू पी एस सी के परिणामों में मध्य प्रदेश के दो युवाओं के टॉप-10 में स्थान बनाने पर खुशी जताई. उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान भोपाल के ईशान को 5वीं रैंक और धार के प्रक्षल को 8वीं रैंक हासिल करने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के युवा देश-दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. डॉ यादव ने गेहूं के संबंध में भी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसान हितैषी है. डॉ यादवने यूपीएससी में राज्य के अन्य सफल हुए उम्मीदवारों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

सफल उम्मीदवार प्रदेश का नाम भी कर रहे हैं रोशन

38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान

तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 6 मार्च. होली के बाद तेज धूप के चलते प्रदेश में तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जिसके चलते भीषण गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है. आगामी दिनों में लोगों को और अधिक गर्मी से जूझना पड़ सकता है. नर्मदापुरम में तापमान 38 डिग्री को टच कर गया.

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटो में, अधिकतम तापमानों में सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में सामान्य से 20° से 30° तक अधिक रहा. नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर संभागों के जिलों में सामान्य से 3.3° से. 4.8° से. अधिक रहा. शेष सभी संभागों के जिलों में सामान्य रहा. इसके साथ ही रीवा, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में सामान्य से 1.8° से. - 2.5° से. अधिक रहा, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में सामान्य से 3.1° से. - 36° से. तक काफी अधिक रहा.

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ऊपरी वायु चक्रवातीय परिसंचरण अब उत्तर-पश्चिम ओडिशा और निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊँचाई पर सक्रिय है. एक ट्रफ, उत्तर-पश्चिम ओडिशा और निकटवर्ती क्षेत्रों पर सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण से उत्तर छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश तक माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊँचाई पर विस्तृत है. उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, लगभग 213 किमी/घंटा की गति से माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊँचाई पर उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर बह रहीं है.

नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद नई रेल लाइन को मिली मंजूरी

380 किमी परियोजना का होगा फाइनल सर्वे

नीमच. आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करीब 380 किलोमीटर लंबी नीमच- बांसवाड़ा- दाहोद- नंदुरबार नई रेल लाइन के लिए अंतिम सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की मंजूरी दे दी है. यह प्रस्तावित रेल परियोजना नीमच (मध्य प्रदेश), बांसवाड़ा (राजस्थान), दाहोद (गुजरात) और नंदुरबार (महाराष्ट्र) सहित आदिवासी बहुल क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. रेल मंत्री के अनुसार यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी. इससे न केवल दूरदराज के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. बांसवाड़ा क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध है. यहां मैंगनीज, डोलोमाइट, चूना पत्थर, सोना, तांबा और क्वार्टजाइट जैसे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. रेल लाइन बनने से माल ढुलाई आसान होगी और इन खनिजों की मांग बढ़ने की संभावना है.

कर्मचारी नेताओं का सरकार से अनुरोध

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील न करने की कर्मचारियों की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 6 मार्च. मध्यप्रदेश के दो प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि नए नियुक्त कर्मचारियों को सेवा के पहले तीन वर्षों में 70त्न, 80त्न और 90त्न स्टाइपेंड देने संबंधी नियम को निरस्त करने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील न की जाए.

मध्यप्रदेश मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ और मध्यप्रदेश निगम मंडल कर्मचारी महासंघ ने कहा कि इस फैसले के विरुद्ध अपील करना असंवेदनशील कदम होगा और इससे सरकार व कर्मचारियों के बीच संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हस्तक्षेप कर अनावश्यक मुकदमेबाजी रोकने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इससे राहत मिलने की संभावना बेहद कम है. संगठनों ने वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें हर प्रतिकूल आदेश के खिलाफ अपील करने की प्रवृत्ति से बचने की सलाह दी गई थी.

2010 के राज्य सरकार के उस परिपत्र का हवाला दिया गया, जिसमें विभागों को जिम्मेदार वादकारी की भूमिका निभाने की बात कही गई थी. उन्होंने चेतावनी दी कि अपील करने से सरकार की कर्मचारी हितैषी छवि को नुकसान पहुंचेगा.

UPSC 2025

टॉप 5 में भोपाल के ईशान

भोपाल, 6 मार्च. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईशान भटनागर ने UPSC 2025 के परिणाम में टॉप-5 स्थान हासिल कर शहर और प्रदेश का मान बढ़ाया है.

फिलहाल वे नागपुर में इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) की ट्रेनिंग (IRS Training) कर रहे हैं. इससे पहले भी वे PSC में चयनित होकर IRS के लिए चुने गए थे, लेकिन इस बार टॉप रैंक लाकर उन्होंने IAS बनने का रास्ता तय कर लिया है. ईशान की मां, प्रोफेसर विनीता धौंढ़ियाल भटनागर ने अपने पुत्र की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि रिज़ल्ट वाले दिन वे बेटे से मिलने नागपुर पहुंचीं. उनका कहना था कि यदि परिणाम उम्मीद के अनुसार न आता, तो वे उनके साथ रहकर हौसला बढ़ाना चाहतीं. लेकिन परिणाम उम्मीद से कई गुना बेहतर आया और परिवार ने इस खुशी को मिलकर मनाया. उन्होंने कहा कि भोपाल से उनका गहरा जुड़ाव है और यह उपलब्धि पूरे शहर के लिए गर्व का

अशोकनगर के चितवन की 17वीं रैंक

परिणाम आने पर चितवन ने दी परिवार को सूचना, परिवार में खुशिया

अशोकनगर. मन ने यदि कुछ बनने और करने का दृढ संकल्प कर लिया तो पूरी कायनत भी उसे उसके मुकाम तक ले जाती है, ऐसा ही दृढ संकल्प उस समय साकार होता नजर आया, जब यूपीएससी के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें शहर के सोनी कालोनी निवासी चितवन जैन यूपीएससी की परीक्षा में देशभर में 23 वीं रैंक हासिक करते हुए आईएएस अधिकारी का प्राप्त किया है.

परिणाम आने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पूरा परिवार में खुशी का महौल देखा गया और वह एक दूसरे को मिठाई बांटकर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए. दरअसल शुक्रवार को यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया गया. जिसमें अशोकनगर के 23 वर्षीय चितवन जैन ने 17वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी का पद प्राप्त किया है.

धार. धार जिले के बाग के छात्र पक्षाल जैन ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 8वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. पक्षाल की इस सफलता से उनके परिवार और पूरे बाग में उत्सव का माहौल है. कपड़ा व्यापारी नीलेश जैन और गृहिणी दीप्ति जैन ने बताया कि पक्षाल शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि रहे हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बाग से प्राप्त की और इंदौर से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद आईआईटी कानपुर से फाइनेंस में डिग्री ली. तकनीकी शिक्षा के बाद उन्होंने देश सेवा के लक्ष्य के साथ साल 2022 में दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी. पक्षाल की छोटी बहन ने उनकी सफलता के पीछे के संघर्ष को साझा करते हुए बताया कि वे दिनभर में मात्र 5 घंटे की नींद लेते थे. शेष सारा समय वे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए व्यतीत करते थे.

सृष्टि को 5वीं कोशिश में मिली यूपीएससी में कामयाबी

ग्वालियर. मुरार इलाके की चिक संतर निवासी सृष्टि गोयल ने यूपीएससी परीक्षा 2025 में ऑलइंडिया रैंक 160 हासिल की है. सृष्टि गोयल के पिता सुनील गोयल का सोने-चांदी का व्यापार है.

सृष्टि गोयल ने बताया कि वह आईआईटी में नहीं जा पायी. इसलिये उन्होंने यह रास्ता चुना है. अपनी 5वीं कोशिश में कामयाब हुई. कोचिंग के बारे में कहा है कि उन्होंने मेन्स के लिये टेस्ट पेपर्स पर विश्वास किया है.

शिवपुरी के दीपक को 563वीं रैंक मिली

शिवपुरी के दीपक कोरकू ने सिविल सेवा परीक्षा में 563वीं रैंक हासिल की है.

कृष्णा गोयल ने 300वीं आल इंडिया रैंक हासिल की है

शिवपुरी के धंधेरा ग्राम के भूपेंद्र धाकड़ पुत्र महेश कुमार धाकड़ का भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए चयन हुआ है.

गेहूं पर निर्णय किसानों के हित में लिया

10 मार्च तक बढ़ी पंजीयन तिथि

भोपाल, 6 मार्च. किसानों की सुविधा और हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा यह निर्णय लिया गया है. इससे अधिक से अधिक किसान अपना पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. मंत्री श्री राजपूत ने इस किसान हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागलवाड़ी में आयोजित कृषि कैबिनेट बैठक के पश्चात यह निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं.

12 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

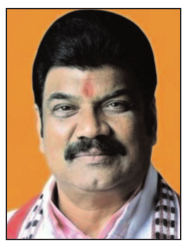

मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अब तक 12 लाख 4 हजार 708 किसानों ने पंजीयन करा लिया है. जिला श्योपुर में 9428, खंडवा में 23017, दमोह में 21390, नरसिंहपुर में 24968, शहडोल में 4710, खरगोन में 11945, कटनी में 25497, रतलाम में 30466, सागर में 46731, राजगढ़ में 65029, शिवपुरी में 7633, डिण्डोरी में 2281, धार में 34283, बुरहानपुर में 206, विदिशा में 62996, मऊगंज में 2727, दतिया में 7420, गुना में 11984, मण्डला में 13391, रीवा में 23380, आगर मालवा में 31318, पन्ना में 11994, जबलपुर में 25698, नीमच में 8122, सीहोर में 80036, बालाघाट में 1766, सिंगरौली में 2811, अलीराजपुर में 248, मैहर में 8625, पांढुर्णा में 305, सिवनी में 35081, भोपाल में 27663 और भिण्ड में 6471 किसानों ने पंजीयन कराया है.

मां की मौत को लेकर युवक ने रोका सीएम का काफिला

इंदौर. इंदौर में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान एक युवक ने अपनी मां की मौत के मामले में न्याय की मांग करते हुए उनका काफिला रोक लिया. बताया गया कि करीब पांच महीने पहले मंजू चौहान को सर्दी-खांसी की शिकायत के चलते एक निजी क्लिनिक पर बीएचएमएस डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन और बॉटल लगाई गई थी. इसके बाद उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मृतका के बेटे रोहन ने न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का काफिला रोक दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवक से बात की और मामले में हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद काफिला आगे बढ़ गया.

अभियान : ट्रेनों में अवैध सामग्री की रोकथाम

भोपाल मंडल में विशेष संयुक्त अभियान

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 6 मार्च. रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडिंग की रोकथाम, खानपान सामग्री की गुणवत्ता जाँच लगातार की जा रही है.

ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ, लिनेन स्टाफ, पेंट्री/ कैटरिंग स्टाफ तथा वेंडरों द्वारा अवैध रूप से शराब, गुटखा, सिगरेट आदि उपलब्ध कराने की संभावित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से भोपाल मंडल में दिनांक 2 मार्च से आगामी 15 दिनों तक विशेष संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में वाणिज्य विभाग, मेकैनिकल विभाग तथा रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न ट्रेनों में जांच की जा रही है.

अभियान के अंतर्गत ट्रेनों में कार्यरत ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ, लिनेन स्टाफ, पेंट्री/ कैटरिंग स्टाफ तथा वेंडरों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की अवैध वस्तुओं की उपलब्धता पर रोक लगाई जा सके और रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं अनुशासित यात्रा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.

जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति अथवा एजेंसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है तो उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. रेल प्रशासन ने यात्रियों से भी अपील की है कि यदि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री की जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित रेलवे अधिकारियों अथवा रेल सुरक्षा बल को सूचित करें.

मुद्दा किसानों का कर्ज और समस्याएं बढ़ने के आरोप

'कृषि कल्याण वर्ष' पर पटवारी के सवाल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 6 मार्च.मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा घोषित कृषि कल्याण वर्ष के दावों पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के किसान आज भी अधूरे वादों, प्रशासनिक लापरवाही और कृषि विकास के लिए निर्धारित धन के सही उपयोग न होने के कारण परेशान हैं.

भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन पिछले दो दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को केवल वादों के सहारे भ्रमित करती रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बार-बार खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसानों का कर्ज और आत्महत्याएँ बढ़ी हैं. राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय किसानों से किए गए तीन प्रमुख वादों को भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है. इनमें सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, धान का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 2,700 रुपये प्रति क्विंटल देने का आश्वासन शामिल था.

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के लगभग 97 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और कृषि विभाग में करीब 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, जिससे किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है। पटवारी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में धन के उपयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 44,891.56 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 32,678.03 करोड़ रुपये ही जारी किए और प्राप्त राशि का लगभग 40 प्रतिशत खर्च ही नहीं किया गया। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद कई कृषि योजनाओं में शून्य आवंटन किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाओं का ब्यौरा तलब

हाईकोर्ट ने विस्तृत विवरण पेश करने के दिए हैं निर्देश

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित सरकारी स्कूलों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत विवरण पेश करने के निर्देश दिए हैं.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में केवल राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों की स्थिति का भी पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है. युगलपीठ ने मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की है. दरअसल, जबलपुर के करौंदी स्थित कैंट स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर प्रकाशित एक समाचार के आधार पर हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को स्वत-संज्ञान लिया था.

स्थानीय निकाय चला रहा है स्कूल

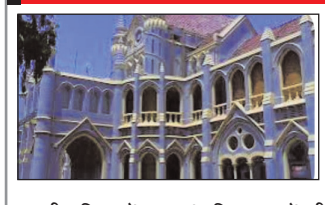

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि संबंधित स्कूल राज्य सरकार के बजाय स्थानीय निकाय द्वारा संचालित किया जा रहा है. इस पर युगलपीठ ने निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों की मौजूदा स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए.